services in these areas. In respect of existing post offices also, some offices which were curtailed or closed in the Kashmir Valley due to unavoidable reasons are being reopened in a phased manner.

A target of 89 Panchayat Sanchar Sewa Kendras has also been allocated to Himachal Pradesh and Uttar Pradesh during the annual plan 1995-96. All the Panchayat Sanchar Sewa Kendras in Himachal Pradesh and some in Uttar Pradesh may be opened in the hilly areas. Further, the department's programme of modernisation, particularly through computer-based counter machines also cover selected post offices located in hilly and tribal areas where some of the office have been fully modernised by optimising the benefits of these counter machines. The department's programme for VSAT centres in selected hilly and tribal areas for expediting transfer of funds and providing other useful services. Efforts to provide basic infrastructure in respect of office buildings and staff quarters also extend to such areas.

(c) The regular measures for improvement of efficiency of service cover all offices and services in the country. In respect of new post offices to be opened, the department however, follows liberalised norms providing subsidy upto 85% of coast for hilly and tribal areas.

शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को सीमित करना

979. **श्री सोमपाल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके विस्तृत कारण क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा शिशुओं के लिए तैयार किए जा रहे दूध उत्पादों और दूध पाउडर की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर और अन्य डाक सुविधाओं से विहीन गांव

980. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है जहां न तो डाकघर हैं और न ही लेटरबाक्स;

(ख) क्या दूरदराज के गांवों में डाक-टिकटों और अन्य डाक सामग्री की सदैव कमी रहती है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कितने गांवों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के सभी गांवों में कब तक डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के (श्री सुखराम): राज्य मंत्री (क) देश में बिना डाकघर और लैटर बाक्स वाले गांवों की संख्या, 31.03.1995 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः विवरण। और 11 में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दूरदराज के इलाकों के डाकघरों में डाक-सामग्री की हमेशा कमी रहती है। कभी-कभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरदराज के इलाकों में थोड़े समय के लिए कतिपय मदों की कमी हुई थी।

(ग) देश के गांवों में, वर्ष 1995-96 के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) देश के सभी गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का लक्ष्य निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार गांवों में डाकघर खोलना है बशर्ते कि जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।